

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 775/2024

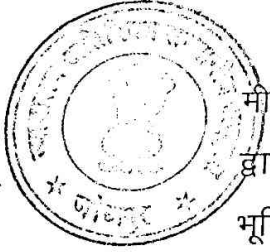
आईदानराम पुत्र मुकनाराम व अन्य
बनाम

राज0 राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा (बाड़मेर)

दिनांक 4.11.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1950 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा (बाड़मेर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 132, 136 आरएलआर एक्ट के तहत पारित आदेश क्रमांक: राजस्व/2025/439 दिनांक 01.10.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्राथी-जोराराम पुत्र हरिराम विश्नोई की ओर से जरिये अधिवक्त: केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील सेड़वा स्थित ग्राम शौभाला दर्शान के खसरा नम्बर 340 रकबा 2.2662 हैक्टर भूमि में से 0.0242 हैक्टर भूमि की किस्म राजस्व रेकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्टा) ट्रेस में दुरुस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त खसरान की भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि है, जो बिना किसी मुआवजे के वंचित व बेदखल हो रहे हैं। उक्त प्रस्ताव ग्रा0पं0 शौभाला दर्शान की मांग पर तहसीलदार सेड़वा के आवेदन व अनुशंशा पर अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में कदीमी रास्ता बताते हुए पारित करवा लिया गया है, जबकि मौके पर कोई रास्ता चलायमान नहीं है और न ही प्रस्तावित स्थल पर रास्ता दर्ज करने की कोई आवश्यकता है। क्योंकि उक्त खसरान के चिपते प्रस्तावित रास्ते से लगती गै0मु0 आबादी भूमि है, जो चारों तरफ से सड़क मार्ग एवं अन्य मार्गों से जुड़ी हुई है। तहसीलदार का आवेदन कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड से भिन्न तथ्यों पर आधारित है। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही उसकी सहमति ली गई। आवेदन सेटलमेंट की कार्यवाही संवत् 2012 में पूर्ण होने के 65 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया है। अपीलाधीन आदेश राज0 भू राजस्व (भूअभिलेख) के नियम 58(3) व अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी कर एकतरफा पारित किया गया है। तहसीलदार को भू



aku
5/11

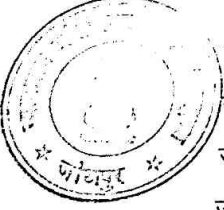
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अर्जन की सम्यक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन भूमि को रास्ते में परिवर्तन करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, इस कारण उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है। राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकार, खातेदार की सहमति के बिना समाप्त करने के प्रावधान नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर विधिविरुद्ध पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में केवियटर अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त रास्ता ग्रा०पं० शौभाला दर्शान के प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 17.9.25 के क्रम में तहसीलदार सेड़वा के पत्र क्रमांक 506 दिनांक 19.9.25 द्वारा प्रस्तावित किया गया। जो ग्राम शौभाला दर्शान की 100-110 रहवासी ढाणियों को ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ता है। मौके पर सी.सी. सड़क व कदीमी रास्ता चल रहा है। जो गुल्लेकीवेरी से विश्वकर्मा नगर जाने वाली मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है व उप स्वास्थ्य केन्द्र शौभाला दर्शान को सड़क से जोड़ता है। मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 17.9.25 में व्यापक जनहित के दृष्टिगत उक्त निजी खातेदारी भूमि में से परम्परागत चालू स्थाई रास्ते की गै०मु०रास्ते के रूप में दर्ज राजस्व अभिलेख/आवंटन किये जाने उचित होने का उल्लेख है। अपीलाधीन आदेश राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राज० जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16 एवं 30.9.21 तथा विधिक नियमों एवं प्रावधानों के तहत पारित किया गया। अपीलार्थीगण यदि उक्त प्रकरण में अपनी सुनवाई चाहता है, तो इसे अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही ग्रा०पं० शौभाला दर्शान की मांग एवं तहसीलदार सेड़वा के प्रस्ताव पर की गई है। अपीलाट का कथन है कि उक्त खसरान के चिपते प्रस्तावित रास्ते से लगती गै०मु० आबादी भूमि है, जो चारों तरफ से सड़क मार्ग एवं अन्य मार्गों से जुड़ी हुई है। तहसीलदार का आवेदन कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड से भिन्न तथ्यों पर आधारित है। मौके पर कोई रास्ता चलायमान नहीं है और न ही प्रस्तावित स्थल पर रास्ता दर्ज करने की कोई आवश्यकता है। प्रकरण में अपीलाट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया




du
4/11

सरिता राजनीय आयुक्त
जयपुर

गया और न ही उसकी सहमति ली गई। अतः दोनो पक्षों की सहमति से अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, प्रकरण अपीलांट्स की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक: राजस्व/2025/439 दिनांक 01.10.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण *अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं संबंधित खातेदारों/सह-खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 4.11.25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर फैसल शुमार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।


(सुनिता चौधरी) 4/11/25
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त जयपुर
जयपुर